Impact Factor (SJIF): 6.126 E-ISSN: 2583-1615, P-ISSN: 3049-3498

International Journal of Research in Academic World

Received: 26/September/2025 **IJRAW:** 2025; 4(11):104-106 **Accepted:** 08/November/2025

युवा राजनीति और सोशल मीडिया: लोकतांत्रिक भागीदारी का नया मॉडल

***[1]डॉ. संजय भारद्वाज**

*[1]एसोसिएट प्रोफेसर, पोलिटिकल साइंस विभाग, राजकीय महाविद्यालय, परबतसर, राजस्थान, भारत।

सारांश

यह शोध-पत्र युवा राजनीति और सोशल मीडिया के अंतःसंबंध को समझने का प्रयास करता है, विशेष रूप से इस दृष्टि से कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किस प्रकार लोकतांत्रिक भागीदारी के नए मॉडल का निर्माण कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने राजनीतिक चेतना, सूचना-प्रवाह, जनमत-निर्माण और राजनीतिक संवाद की प्रक्रियाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है, जिससे युवा वर्ग अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार के रूप में उभर रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफ़ॉर्म युवाओं को अपनी राजनीतिक पहचान व्यक्त करने, विरोध दर्ज कराने, नागरिक जागरूकता फैलाने और संगठित आंदोलनों को गति देने का अवसर प्रदान करते हैं। यह डिजिटल सक्रियता पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं को चुनौती देती है और प्रतिनिधिक लोकतंत्र को भागीदारी आधारित, विकेन्द्रीकृत तथा अधिक पारदर्शी बनाती है।

हालाँकि, सोशल मीडिया-आधारित युवा राजनीति कई चुनौतियों से भी घिरी है—जैसे सूचना का अतिप्रवाह, भ्रामक सामग्री, ट्रोल संस्कृति, डिजिटल विभाजन और राजनीतिक ध्रुवीकरण। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने युवाओं के राजनीतिक व्यवहार को नए आयाम प्रदान किए हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी को अधिक खुला, समावेशी और संवादोन्मुख बनाया है। यह शोध-पत्र डिजिटल युग में युवा राजनीति के बदलते स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करता है और यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया भारत सहित वैश्विक लोकतंत्रों में राजनीतिक सहभागिता का एक प्रभावी नया मॉडल बनकर उभरा है।

मुख्य शब्द: युवा राजनीति, सोशल मीडिया, डिजिटल लोकतंत्र, राजनीतिक भागीदारी, जनमत-निर्माण, डिजिटल सक्रियता।

1. प्रस्तावना

21वीं सदी में वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य डिजिटल तकनीक के प्रभाव से एक क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विशेष रूप से भारत जैसे जनसंख्या-बहुल लोकतांत्रिक देश में डिजिटल माध्यमों ने राजनीतिक संचार, जनभागीदारी और जनमत-निर्माण की प्रक्रिया को नए आयाम दिए हैं। इस परिवर्तन के केंद्र में युवा वर्ग है, जिसकी आयु 18–35 वर्ष के बीच है और जो न केवल सोशल मीडिया का सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता है, बल्कि राजनीतिक विमर्श का प्रमुख प्रेरक भी बन गया है।

जहाँ पहले युवाओं की राजनीतिक भागीदारी मतदान, सभाओं, जुलूसों और छात्र राजनीति तक सीमित थी, वहीं आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X), यूट्यूब और व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म नए प्रकार की राजनीतिक संलग्नता को जन्म दे रहे हैं। ऑनलाइन याचिकाएँ, डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, हैशटैग मूवमेंट, वायरल वीडियो, और ई-आंदोलन (E-Movements) युवाओं को केवल दर्शक नहीं रहने देते, बल्कि उन्हें सक्रिय नागरिक—अभियानकर्ता, विश्लेषक और नीति-प्रभावक—बनाते हैं।

भारत में युवा वर्ग अब राजनीतिक सूचना का मुख्य उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि संचार का उत्पादक (Content Producer) भी बन चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का प्लेटफ़ॉर्म मानना अपर्याप्त है; यह लोकतांत्रिक ढांचे का एक सशक्त स्तंभ बनकर उभरा है, जहाँ राजनीतिक विचारों का विनिमय, जनसरोकारों का विस्तार और नीतिगत बहसों का लोकतंत्रीकरण संभव हो रहा है। इसी संदर्भ में "युवा राजनीति और सोशल मीडिया" का अध्ययन न केवल समकालीन राजनीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भविष्य के लोकतांत्रिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रियाओं और नागरिक सहभागिता के नए मॉडल को भी रेखांकित करता है।

2. सोशल मीडिया: लोकतांत्रिक मॉडल का नया आधार

डिजिटल युग में सोशल मीडिया लोकतंत्र के पारंपरिक ढांचे को नई दिशा देने वाला सबसे प्रभावशाली माध्यम बनकर उभरा है। यह केवल सूचना विनिमय का साधन नहीं रहा, बल्कि विचारों, पहचानों और राजनीतिक सहभागिता का एक सशक्त प्लेटफ़ॉर्म बन गया है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को गतिशील, सहभागी और विकेन्द्रीकृत बनाया है, जहाँ प्रत्येक नागरिक—विशेष रूप से युवा—मत, विचार, आलोचना और सक्रियता के माध्यम से लोकतांत्रिक विमर्श को आकार देता है। इसने राजनीतिक निर्णय-निर्माण में सहभागिता के नए रास्ते खोले हैं, जिससे लोकतंत्र अब केवल प्रतिनिधिक संस्था न रहकर एक निरंतर संवादात्मक प्रक्रिया

***Corresponding Author:** डॉ. संजय भारद्वाज

में बदल गया है। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया आधुनिक लोकतांत्रिक मॉडल का ऐसा आधार बन चुका है, जो न केवल राजनीतिक जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि जनमत निर्माण, सामाजिक आंदोलनों और नीति-विमर्श को भी नए आयाम प्रदान करता है।

i). **सूचना-प्रवाह और राजनीतिक जागरूकता:** सोशल मीडिया ने राजनीतिक सूचना के प्रवाह को अभूतपूर्व गति और व्यापकता प्रदान की है। पहले जहाँ राजनीतिक समाचार पारंपरिक मीडिया—जैसे अख़बार, रेडियो और टीवी—तक सीमित थे, वहीं आज डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कुछ ही मिनटों में लाखों युवाओं तक सूचनाएँ पहुँचाने में सक्षम हैं। ट्विटर (X) पर ट्रेंड होते हैशटैग, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब विश्लेषण, और फेसबुक पोस्ट राजनीतिक घटनाओं को तत्काल सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना देते हैं। इस त्वरित सूचना-प्रवाह ने युवा वर्ग को राजनीतिक रूप से अधिक सचेत, तर्कसंगत और प्रतिक्रियाशील बनाया है।

सूचना की इस सहज उपलब्धता ने न केवल युवाओं की राजनीतिक समझ को गहराया है, बल्कि उन्हें नीति-निर्माण, चुनावी बहसों, सामाजिक आंदोलनों और नागरिक अधिकारों के मुद्दों में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा भी दी है। परिणामस्वरूप, युवा अब राजनीति के निष्क्रिय दर्शक नहीं, बल्कि डिजिटल नागरिकता के सक्रिय प्रतिनिधि बनकर उभर रहे हैं।

ii). **राजनीतिक पहचान और राय-निर्माण:** सोशल मीडिया ने युवाओं की राजनीतिक पहचान को गढ़ने और अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। युवा फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, ट्विटर (X) थ्रेड्स, यूट्यूब व्लॉग्स और ब्लॉग के माध्यम से अपनी राजनीतिक विचारधारा, मूल्य-मान्यताओं और सामाजिक चिंताओं को खुलकर व्यक्त करते हैं। इस प्रकार एक नया डिजिटल सार्वजनिक क्षेत्र (Digital Public Sphere) आकार लेता है, जहाँ विविध राजनीतिक दृष्टिकोणों पर विचार-विमर्श, तर्क-वितर्क और वैचारिक आदान-प्रदान संभव हो पाता है।

इस डिजिटल संवाद ने युवाओं को न केवल अपनी राय बनाने में सक्षम किया है, बल्कि उन्हें सरकार की नीतियों पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया देने, असहमति दर्ज कराने और वैकल्पिक राजनीतिक विमर्श को आगे बढ़ाने का भी अवसर दिया है। इस प्रक्रिया में सोशल मीडिया युवाओं के लिए "राजनीति का लोकतंत्रीकरण" करता है, जहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज़ को सार्वजनिक क्षेत्र में समान रूप से रख सकता है।

iii). **डिजिटल सक्रियता और जन-आंदोलन:** सोशल मीडिया ने युवा राजनीति को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा; उसने सक्रिय राजनीतिक हस्तक्षेप को भी नई दिशा दी है। भारत में कई महत्वपूर्ण आंदोलनों और सामाजिक अभियानों ने सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जन-समर्थन प्राप्त किया, जिनमें—निर्भया आंदोलन (2012), नेट न्यूट्रैलिटी अभियान, CAA–NRC विरोध प्रदर्शन, तथा किसान आंदोलन (2020–2021) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल माध्यम स्थानीय असंतोष को राष्ट्रीय स्तर के जन-आंदोलन में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। हैशटैग कैंपेन, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन समूह, डिजिटल पोस्टर और वायरल वीडियो ने युवाओं को संगठित करने, मुद्दों को व्यापक बनाने और जनमत तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

इस प्रकार डिजिटल सक्रियता (Digital Activism) युवाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप का एक नया और प्रभावशाली मॉडल प्रस्तुत करती है, जो न केवल सड़क पर होने वाले आंदोलनों को सशक्त बनाती है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में व्यापक और त्वरित सहभागिता को भी सुनिश्चित करती है।

3. युवा राजनीति के डिजिटल आयाम

डिजिटल क्रांति ने युवा राजनीति को नए आयाम दिए हैं, जिनके माध्यम से न केवल राजनीतिक संवाद, बल्कि राजनीतिक क्रिया-व्यवहार भी तीव्र और व्यापक हुआ है। सोशल मीडिया ने राजनीतिक भागीदारी के कई नवीन मॉडल विकसित किए हैं, जिनमें हैशटैग आधारित आंदोलन, साइबर-प्लेटफ़ॉर्म पर चुनावी अभियान और ऑनलाइन नागरिक-सहभागिता विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये आयाम इस बात का प्रमाण हैं कि डिजिटल युग में राजनीतिक सक्रियता केवल भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं रही; बल्कि तकनीक-संचालित सहभागिता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक सुलभ, समावेशी और त्वरित बनाया है।

i). हैशटैग राजनीति (Hashtag Activism)

पिछले एक दशक में हैशटैग राजनीति ने युवाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है। #MeToo, #BlackLivesMatter, #FarmersProtest, और भारत में #JusticeFor… जैसे अभियान इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि एक साधारण-सा हैशटैग लाखों लोगों को जोड़ सकता है और तुरंत अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन सकता है।

हैशटैग आंदोलन कुछ प्रमुख विशेषताओं के कारण प्रभावी बनते हैं:

- विचार और संदेश का त्वरित प्रसार
- भावनात्मक और राजनीतिक एकजुटता का निर्माण
- नेतृत्व-विहीन (leaderless) और विकेन्द्रीकृत आंदोलन का उभार
- परंपरागत मीडिया की सीमाओं को तोड़कर नई कथा प्रस्तुत करना

इस प्रकार हैशटैग राजनीति युवाओं के लिए कम लागत वाला, तेज और प्रभावी राजनीतिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुकी है।

ii). साइबर-प्लेटफ़ॉर्म और चुनावी राजनीति

चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। आज राजनीतिक दल युवाओं तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया रणनीति, डिजिटल विज्ञापन, वीडियो संदेशों, लाइव-इंटरेक्शन और लक्षित कैंपेनिंग (Targeted Campaigning) का व्यापक उपयोग कर रहे हैं।

इसके कुछ स्पष्ट संकेत हैं:

- राजनीतिक दलों की IT सेल का सक्रिय होना
- डेटा-आधारित चुनाव प्रचार
- माइक्रो-टार्गेटिंग के माध्यम से अलग-अलग युवा समूहों तक पहुँच
- बॉट्स और एल्गोरिथ्म का उपयोग संदेशों को बढ़ाने के लिए

इन तत्वों ने चुनावी राजनीति को पारंपरिक जनसभाओं से आगे बढ़ाकर एक ऐसी डिजिटल लड़ाई में बदल दिया है जहाँ राजनीतिक नैरेटिव अक्सर ऑनलाइन बनते और बिगड़ते हैं। इससे युवाओं की चयन-प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे डिजिटल सामग्री और ट्रेंड्स के माध्यम से अपने राजनीतिक निर्णय निर्मित करते हैं।

iii). ऑनलाइन याचिकाएँ और डिजिटल नागरिकता

Change.org, Jhatkaa.org और अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने राजनीतिक भागीदारी को औपचारिक लोकतांत्रिक संरचना से बाहर

निकलकर दैनिक जीवन के मुद्दों तक पहुँचाया है। ऑनलाइन याचिकाएँ युवाओं को—

- किसी भी मुद्दे पर हस्ताक्षर कर समर्थन देने,
- स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय विमर्श में बदलने,
- नीति-निर्माताओं पर दबाव बनाने,
- और नागरिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों पर अपनी आवाज उठाने का अवसर प्रदान करती हैं।

ऑनलाइन याचिका संस्कृति से लोकतंत्र का विकेन्द्रीकरण हुआ है, जहाँ हर नागरिक अपने मोबाइल से ही राजनीतिक प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बन सकता है। यह डिजिटल नागरिकता (Digital Citizenship) युवाओं को राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त, जागरूक और भागीदारी-उन्मुख बनाती है।

4. सोशल मीडिया आधारित लोकतांत्रिक मॉडल की सीमाएँ — विश्लेषण

यद्यपि सोशल मीडिया युवा राजनीति और लोकतांत्रिक भागीदारी का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है, फिर भी इसके कई अंतर्निहित सीमाएँ लोकतांत्रिक आदर्शों को चुनौती देती हैं। फेक न्यूज़ और सूचना का प्रदूषण तेज़ी से फैलते हुए तथ्यों को विकृत करता है और समाज में अविश्वास तथा ध्रुवीकरण को बढ़ाता है। ट्रोल कल्चर और हेट स्पीच राजनीतिक विमर्श को मर्यादाहीन बनाकर स्वस्थ बहस की संभावना को कम करते हैं, जिससे कई युवा राजनीतिक अभिव्यक्ति से पीछे हट जाते हैं। डिजिटल विभाजन की समस्या तकनीकी पहुँच की असमानता को उजागर करती है, जिसमें ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर तथा डिजिटल रूप से कम शिक्षित युवाओं की लोकतांत्रिक सहभागिता सीमित रह जाती है। साथ ही, सोशल मीडिया के एल्गोरिद्म सूचना की प्राथमिकता तय करते हैं, जो राजनीतिक राय-निर्माण पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है और लोकतंत्र में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के सिद्धांतों को कमजोर करता है। इन सभी सीमाओं से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया आधारित लोकतांत्रिक मॉडल संभावनाओं के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी लेकर आता है, जिन्हें समझना और समाधान की दिशा में कार्य करना अत्यंत आवश्यक है।

i). **फेक न्यूज़ और सूचना का प्रदूषण:** सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती फेक न्यूज़ का तीव्र प्रसार है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर बिना किसी सत्यापन प्रक्रिया के सूचना साझा हो जाती है, जिससे झूठे राजनीतिक नैरेटिव, अफवाहें और दुष्प्रचार तेजी से फैलते हैं। यह "सूचना का प्रदूषण" न केवल युवाओं की राजनीतिक समझ को प्रभावित करता है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद को भी दिग्भ्रमित करता है। चुनावों के दौरान गलत सूचनाओं का इस्तेमाल विशेष समूहों को प्रभावित करने या वोटों को ध्रुवीकृत करने के लिए किया जाता है। इससे लोकतांत्रिक निर्णय-निर्माण की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ii). **ट्रोल कल्चर और हेट स्पीच:** डिजिटल राजनीतिक सक्रियता के साथ-साथ ट्रोलिंग और ऑनलाइन दुश्मनी की संस्कृति भी तेजी से बढ़ी है। राजनीतिक असहमति अक्सर व्यक्तिगत आक्रमण, अपमानजनक भाषा, धमकियों और चरित्रहनन में बदल जाती है। इससे न केवल स्वस्थ राजनीतिक बहस बाधित होती है, बल्कि युवा वर्ग में भय और आत्म-सेंसरशिप का वातावरण बनता है। कई युवाओं—विशेषकर महिलाएँ और अल्पसंख्यक—ऑनलाइन बदसलूकी के कारण राजनीतिक सहभागिता से दूर हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया लोकतांत्रिक समावेशिता के बजाय मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हिंसा का मंच भी बन जाता है।

iii). **डिजिटल विभाजन (Digital Divide):** भारत जैसे देशों में सभी युवाओं के पास स्मार्टफोन, उच्चगति इंटरनेट या पर्याप्त डिजिटल साक्षरता उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण-शहरी अंतर, आर्थिक असमानता और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण बड़ी संख्या में युवा डिजिटल राजनीति की मुख्यधारा से बाहर रह जाते हैं। इससे सोशल मीडिया आधारित लोकतांत्रिक मॉडल में समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। ऑनलाइन राजनीतिक विमर्श में वही लोग शामिल हो पाते हैं जिनके पास डिजिटल संसाधन और तकनीकी दक्षता होती है। इस प्रकार, डिजिटल लोकतंत्र अनजाने में असमानताओं को पुनः स्थापित कर सकता है।

iv). **एल्गोरिथमिक नियंत्रण (Algorithmic Control):** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जटिल एल्गोरिथ्म के माध्यम से यह निर्धारित करते हैं कि कौन-सी सामग्री उपयोगकर्ताओं को दिखाई जाएगी और किसे दबा दिया जाएगा। एल्गोरिथ्म का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक लाभ होता है—जिसके चलते भावनात्मक, सनसनीखेज और ध्रुवीकरण करने वाली सामग्री अधिक प्रसारित होती है। इससे "algorithmic bias" उत्पन्न होता है, जिसमें उपयोगकर्ता को सीमित, पक्षपाती और फिल्टर-बबल आधारित सूचना मिलती है। यह राजनीतिक राय-निर्माण को कृत्रिम रूप से प्रभावित करता है और लोकतंत्र की तटस्थता को चुनौती देता है। इस प्रकार, सूचना की स्वतंत्रता एल्गोरिथ्मिक संरचनाओं के नियंत्रण में होकर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को चुनौती देती है।

5. विश्लेषण (Analysis)

सोशल मीडिया ने युवा राजनीति को अवसरों और चुनौतियों के एक जटिल परिवेश में खड़ा कर दिया है। एक ओर यह लोकतांत्रिक भागीदारी को अभूतपूर्व रूप से समावेशी, त्वरित और प्रभावी बनाता है, जहाँ युवा अपनी आवाज़ सीधे सार्वजनिक क्षेत्र में पहुँचा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म राजनीतिक संवाद को पारदर्शिता, प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया और जनसहभागिता के नए आयाम प्रदान करते हैं, जिससे लोकतंत्र अधिक सहभागितामूलक बनता है। दूसरी ओर, यही माध्यम राजनीतिक विमर्श को उत्तेजना, ध्रुवीकरण और गलत सूचना के जाल में भी फँसाता है। फेक न्यूज़, ट्रोलिंग और एल्गोरिथमिक पक्षपात जैसे मुद्दे लोकतांत्रिक संचार को कमजोर करते हुए युवाओं की राजनीतिक चेतना को भ्रमित कर सकते हैं। इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि डिजिटल युग का लोकतंत्र युवाओं के नेतृत्व में एक नए स्वरूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया सामाजिक आंदोलनों, नागरिक सहभागिता, राजनीतिक नवाचार और जनमत-निर्माण का शक्तिशाली मंच बन चुका है, जो पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं को चुनौती देते हुए लोकतंत्र की नई संभावनाओं को जन्म देता है।

संदर्भ सूची

1. कुमार, अरविंद. भारतीय राजनीति और डिजिटल समाज. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन, 2020.
2. सिंह, राजीव. सोशल मीडिया और युवा राजनीति. लोकभारती प्रकाशन, 2021.
3. चतुर्वेदी, विनोद. भारतीय लोकतंत्र और डिजिटल परिवर्तन. राजकमल प्रकाशन, 2019।